

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1987  
जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है।  
22 माघ, 1947 (शक)

**इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी 2.0**

**1987. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- क. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के अन्तर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है तथा उनकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;
- ख. इन ईएमसी के माध्यम से विशेषकर कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में कुल कितना निवेश आकर्षित हुआ तथा कितने रोजगार सृजित हुए;
- ग. क्या सरकार ने भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे की तैयारी या निवेशकों की रुचि में चुनौतियों की पहचान की है, जिसके कारण क्लस्टर के पूरा होने में देरी हुई है;
- घ. क्या सरकार का एकीकृत सेमीकंडक्टर और घटक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए ईएमसी योजना को सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन और उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के साथ समेकित करने का प्रस्ताव है; और
- ङ. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कौन-से कदम उठाए हैं कि दावणगेरे जैसे टियर-2 जिलों सहित छोटे शहरों को योजना के आगामी चरणों में शामिल किया जाए?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (ङ): एमईआईटीवाई ने भारत में विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से अप्रैल 2020 में संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना को अधिसूचित किया है। यह योजना निवेश को आकर्षित करेगी, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी, रोजगार पैदा करेगी और तैयार औद्योगिक भूखंडों और रेडी-बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड/प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं सहित साझा बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं के साथ समर्पित क्लस्टरों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके ईएसडीएम क्षेत्र को बढ़ावा देगी।

इस योजना के तहत, कर्नाटक में 2 ईएमसी, तमिलनाडु में 2 ईएमसी और उत्तर प्रदेश में 1 ईएमसी सहित 10 राज्यों में 13 परियोजनाओं (11 ईएमसी और 2 सीएफसी) को मंजूरी दी गई है।

ये ईएमसी 4,399.68 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 5,226.49 करोड़ रुपये है, जिसमें 2,492.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है।

इन परियोजनाओं में 1,46,846 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश और लगभग 1.73 लाख नौकरियों की अनुमानित रोजगार क्षमता है। अब तक, 10,915.84 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 13,682 नौकरियों का सृजन हुआ है।

इसके अलावा, टियर-2 और टियर-3 स्थानों में 8 ईएमसी स्थापित किए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के विकेंद्रीकरण में योगदान दे रहे हैं। ईएमसी परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान द्वारा ईएमसी 2.0 योजना का प्रभाव मूल्यांकन किया गया था। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को एमईआईटीवाई द्वारा राज्य सरकारों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय से लिया गया है।

भारत सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु एक सुविचारित रणनीति अपनाई है। इस रणनीति को सेमीकॉन इंडिया मिशन, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना जैसी पहलों के माध्यम से एक समन्वित एवं एकीकृत नीतिगत ढाँचे के तहत लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए एक समेकित पारितंत्र का विकास करना है।

ईएमसी योजना एक सक्षम वातावरण बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित है, जबकि सेमीकॉन इंडिया मिशन और पीएलआई योजनाएं विनिर्माण और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं। इसलिए, ये योजनाएं संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक-दूसरे की पूरक हैं। सामूहिक रूप से, ये पहल घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती हैं।

विनिर्माण इकाइयों के लिए स्थानों का चयन उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो सहायक नीतियों और व्यापार करने में आसानी के उपायों के आधार पर होता है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध -1

ईएमसी 2.0 योजना के तहत अनुमोदित राज्यवार परियोजनाओं की स्थिति

#	राज्य	स्थान	कार्य- क्षेत्र	परियो जना लागत (₹ करोड़ में)	एमईआई टीवाई योगदान- ऑन (₹ करोड़ में)	निवेश प्रतिबद्ध (₹ करोड़)	जुटाया गया/ग्राउं डेड निवेश (₹ करोड़)	प्रतिबद्ध रोजगार	सृजित रोजगा र
1	आंध्र प्रदेश	ईएमसी - कोप्पर्थी, कडप्पा वाईएसआर	540	748.7 6	350	8,910.00	115.00	28,520	2800
2	छत्तीसगढ़	सीएफसी - टूटा विलेज, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर डिस्ट।	3.23	108.4 3	75	27.18	-	2500	-
3	गुजरात	ईएमसी -टीपी -2 ए, धोलेरा सर, गुजरात	1,026. 82	574.0 3	287.02	99,160.00	400.00	28,787	4300
4	हरियाणा	ईएमसी - आईएमटी सोहना	500	662.0 8	331.04	10,000.00	3100.00	18,000	1800
5	कर्नाटक	ईएमसी - कोटूर - बेलूर, धारवाड़	224.5	179.1 4	89.57	1,512.00	200.00	7,284	200
		ईएमसी - कोचनहल्ली, मैसूर	235.5 5	221.5 4	110.77	1,560.00	500.00	19,500	-
6	महाराष्ट्र	ईएमसी - रंजनगांव-III, पुणे	297.1 1	492.8 5	207.98	2,000.00	637.69	5,000	838
7	तमिलनाडु	ईएमसी - पिल्लैयापक्कम, कांचीपुरम	379.3	424.5 5	212.27	8,737.00	4941.00	14,519	1418
		ईएमसी - मनल्लूर, तिरुवल्लूर	474.3	587.4 7	293.73	4,175.00	500.00	16,900	2000
8	तेलंगाना	सीएफसी - रायदुर्ग गांव, हैदराबाद	1	104.6 3	75	65.72	-	120	16
		ईएमसी - डिविटिपल्ली, महबूबनगर	377.6 5	569.6 6	258.1	7500.00	300.15	10,000	310
9	उत्तर प्रदेश	ईएमसी - सेक्टर 10, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर जिला	206.4	417	144.48	2500.00	222.00	15,000	-
10	उत्तराखंड	काशीपुर	133.8 2	136.3 5	57.78	700.00	-	7,500	-
<b>उप-योग (क)</b>			<b>4,399 .68</b>	<b>5,226 .49</b>	<b>2,492.7 4</b>	<b>1,46,846. 90</b>	<b>10,915.8 4</b>	<b>1,73,63 0</b>	<b>13,682</b>